



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2005/पौष 29, 1926

No. 14]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2005/PAUSA 29, 1926

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2005

सं. 23/11/2004-आर एंड आर (खण्ड-II).—वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए बोली देने की प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। विद्युत खरीद की लागत वितरण लाइसेंसधारियों के लिए सबसे बड़ा लागत अवयव होता है। वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्धी अधिप्राप्ति द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति की समग्र लागत कम करना और विद्युत बाजारों का विकास सुविधाजनक बनाना प्रत्याशित है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा से विद्युत के मूल्यों में कमी हुई है और उपभोक्ताओं को काफी लाभ पहुंचा है।

अधिनियम की धारा 61 और 62 टैरिफ विनियम और उपयुक्त आयोग द्वारा उत्पादन, पारेषण चक्रण और विद्युत की खुदरा बिक्री के टैरिफ निर्धारण की व्यवस्था करती है। अधिनियम की धारा 63 वर्णन करती है कि—

“धारा 62 में कुछ विहित होते हुए भी, उपयुक्त आयोग टैरिफ अपनाएगा अगर ऐसा टैरिफ केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोली देने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।”

ये दिशानिर्देश अधिनियम की धारा 63 के उपरोक्त प्रावधानों के अधीन बनाए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1. वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्धी अधिप्राप्ति का संवर्धन;
2. अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और औचित्य सुविधाजनक बनाना
3. विभिन्न बोलीदाताओं के लिए सूचना संबंधी विषमता को कम करना सुविधाजनक बनाना;
4. विद्युत की अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धी शर्तें सुविधाजनक बनाकर उपभोक्ता का हित संरक्षण;
5. मानकीकरण की वृद्धि और द्विअर्थकता कम करके परियोजनाओं को भूत रूप देने के लिए समय कम करना;
6. विद्युत की उपलब्धता और क्रेताओं के लिए टैरिफ पर निश्चितता सुनिश्चित करते हुए आंतरिक प्रचालनों पर आपूर्तिकर्ताओं को नमनीयता प्रदान करना।

2. दिशानिर्देशों का सीमाक्षेत्र

2.1 ये दिशानिर्देश वितरण लाइसेंसधारियों (अधिप्राप्तिकर्ता) द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित के लिए जारी किए जा रहे हैं:

- (क) 7 वर्ष और उससे अधिक की अवधि के लिए विद्युत की दीर्घावधिक अधिप्राप्ति
- (ख) 7 वर्षों तक परंतु 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मध्यावधिक अधिप्राप्ति।

2.2 दिशानिर्देश निम्नलिखित कार्यतंत्र के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा बेस लोड, पीक लोड और विद्युत की मौसमी आवश्यकता की अधिप्राप्ति के लिए लागू होंगे;

- (i) जहां अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा स्थान, प्रौद्योगिकी अथवा ईंधन निर्दिष्ट नहीं किया जाता है (मामला 1);
- (ii) जल विद्युत परियोजनाओं, भार केंद्र परियोजनाओं अथवा अन्य स्थान विशिष्ट परियोजनाओं और उपलब्ध कैप्टिव खान जैसे विशिष्ट ईंधन आवंटन सहित परियोजनाओं के लिए, जिन्हें अधिप्राप्तिकर्ता टैरिफ-आधारित बोली की प्रक्रिया के अधीन स्थापित करना चाहता है (मामला 2)

2.3 जब तक इन दिशानिर्देशों में स्पष्टतः निर्दिष्ट नहीं हो, इन दिशानिर्देशों के प्रावधान अधिप्राप्तिकर्ता पर बाध्यकारी होंगे। इन दिशानिर्देशों से प्रस्तावित किसी विपणन की दशा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों में बाद में पैरा 5.16 के अधीन निर्दिष्ट की गई है।

2.4 संयुक्त बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक से अधिक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अधिप्राप्ति की अनुमति दी जाएगी। ऐसी संयुक्त अधिप्राप्ति के लिए प्रत्येक अधिप्राप्तिकर्ता इन दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान करेगा। बोलियों के मूल्यांकन में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिप्राप्तिकर्ताओं द्वारा बोलीदाताओं को प्रस्तावित भुगतान सुरक्षा और अन्य वाणिज्यिक शर्तें भिन्न-भिन्न नहीं होंगी। बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्य बोली भी आमंत्रित करने वाले वितरण लाइसेंसधारियों के लिए समान रहेगी।

2.5 बोली प्रक्रिया के लिए अधिप्राप्तिकर्ताओं द्वारा सभी दायित्वों की पूर्ति की गई तभी मानी जाएगी जब प्रत्येक अधिप्राप्तिकर्ता "आरएफपी" में निर्धारित ऐसे दायित्वों की पूर्ति करता है। तथापि, यह बोलीदाता को ऐसी निर्दिष्टि की माफी से नहीं रोकेगा अगर बोलीदाता ऐसा करना उचित पाता है और उसे इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

3. बोली आमंत्रित करने की तैयारी

3.1 बोली प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएंगी:

- (i) बोली प्रलेखीकरण इन दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा और जब तक बोली दस्तावेज केंद्र सरकार द्वारा जारी बोली दस्तावेजों के अनुसार नहीं हो, उपयुक्त विनियामक आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। ऐसे मामलों में, अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा बोली देने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बारे में उपयुक्त विनियामक आयोग को सूचना भेजी जाएगी।
- (ii) इन दिशानिर्देशों में विहित बोली देने की शर्तों से विपथन की दशा में इन दिशानिर्देशों के पैरा 5.16 में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपयुक्त आयोग का अनुमोदन मांगा जाएगा।
- (iii) निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में बोली देने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व उपयुक्त आयोग का अनुमोदन मांगा जाएगा:
 - (क) अधिप्राप्त की जाने वाली क्षमता/ऊर्जा की मात्रा के लिए अगर वह अगले तीन वर्षों के लिए पूर्वानुमानित अतिरिक्त मांग से अधिक हो (मामला 1 और मामला 2 दोनों के लिए)
 - (ख) ईंधन विशिष्ट अधिप्राप्ति पूछताछ के मामले में ईंधन के अंतरण मूल्य के लिए अगर ऐसा मूल्य सरकार, सरकारी अनुमोदित कार्यतंत्र अथवा किसी ईंधन विनियामक द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है (मामला 2 के अधीन)

3.2 जल विद्युत परियोजनाओं अथवा उन परियोजनाओं, जिनके लिए पूर्व-अभिज्ञात कार्यस्थलों का उपयोग किया जाना है, (मामला 2) से दीर्घावधिक अधिप्राप्ति के लिए अधिप्राप्तिकर्ता अथवा अधिप्राप्तिकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोली प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व निम्नलिखित कार्यकलाप पूरे किए जाने चाहिए:

- परियोजना के लिए अपेक्षित कार्यस्थल की पहचान और भूमि अधिग्रहण
- पर्यावरणीय स्वीकृति
- अगर अपेक्षित हो, ईंधन लिंकेज भी बोलीदाता से मांगी जा सकती है
- जल का लिंकेज
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जहां लागू हो उचित जल वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक और भूकंपवैज्ञानिक आंकड़ा।

बोलीदाता स्वयं अपने स्रोतों से भूवैज्ञानिक आंकड़े सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र होगा क्योंकि भूवैज्ञानिक जोखिम परियोजना प्रवर्तक पर होगा।

परियोजना कार्यस्थल घोषित मूल्य पर सफल बोलीदाता को अंतरित किया जाएगा।

3.3 यह सिफारिश की जाती है कि अधिप्राप्तिकर्ता को बोली आमंत्रित करने के पूर्व सुपुर्दगी स्थल पर विद्युत प्राप्त करने के लिए आवश्यक पारेषण स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। तथापि, यह बोली प्रक्रिया के लिए बाध्यकारी शर्त नहीं होगी। जब तक बोली दस्तावेजों में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हो, निकासी और विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण (जहां लागू हो) के लिए पारेषण लिंकेज प्राप्त करना चयनित बोलीदाता का उत्तरदायित्व होगा।

4. टैरिफ संरचना

4.1 इन दिशानिर्देशों के अधीन विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए प्रत्येक भुगतान अवधि (एक महीने से अनधिक) के लिए टैरिफ का भुगतान किया और निपटाया जाएगा। टैरिफ की पृथक् क्षमता और ऊर्जा संघटक वाली बहुभाग टैरिफ संरचना साधारणतया बोली देने का आधार बनेगी। तथापि, मध्यावधिक अधिप्राप्ति के लिए अधिप्राप्तिकर्ता अपने विकल्प पर एकल भाग आधार पर बोलियों की अनुमति दे सकता है और उसे अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफव्यू)/ प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में स्पष्टतया निर्दिष्ट किया जाएगा।

4.2 विशिष्ट ईंधन आवंटन सहित दीर्घावधिक अधिप्राप्ति के मामले में (मामला 2), अधिप्राप्तिकर्ता क्षमता प्रभार और बताई गई निवल उष्मा दर के आधार पर बोलियों आमंत्रित करेगा। निवल उष्मा दर विद्युत स्टेशन की आंतरिक विद्युत खपत को ध्यान में रखते हुए एक्स-बस होगी। ऊर्जा प्रभार निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार देय होगा:

ऊर्जा प्रभार = नई बनाई गई उष्मा दर × निर्धारित उत्पादन × ईंधन का मासिक भारांशित औसत मूल्य / ईंधन का मासिक औसत सकल उष्मीय मान

अगर ईंधन का मूल्य भारत सरकार, सरकारी अनुमोदित कार्यतंत्र अथवा ईंधन विनियामक द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है तो उसे उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित कराया जाना होगा।

कोयला/लिग्नाइट ईंधन के मामले में गौण ईंधन तेल की लागत को क्षमता प्रभार में शामिल किया जाएगा।

- 4.3 टैरिफ केवल भारतीय रूपए में नामोदिष्ट किया जाएगा। विदेशी मुद्रा जोखिम, अगर कोई हो, का वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा। सभी मामलों में पारेषण प्रभार का वहन अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।

क्षमता प्रभार

- 4.4 क्षमता प्रभार का भुगतान रूपए/कि.वा.घं. में बताए गए प्रभारों के अनुसार कि.वा.घं. में वास्तविक उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा और वह मानकीय उपलब्धता (अथवा जल विद्युत स्टेशनों के लिए मानकीय क्षमता सूचकांक) तक सीमित होगा। मानकीय उपलब्धता बोली प्रक्रिया के समय विद्यमान केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट स्तर के अनुरूप लाई जाएगी और उसका संगणन वार्षिक आधार पर किया जाएगा। टैरिफ के क्षमता संघटक में पृथक अवृद्धिकारी (नियत) और वृद्धिकारी (सूचकांकित) संघटक हो सकते हैं। वृद्धिकारी संघटक की वृद्धि के लिए अपनाया जाने वाला सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा और आधार वर्ष बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- 4.5 मानकीय उपलब्धता से अधिक आपूर्ति के लिए क्षमता प्रभार, क्षमता प्रभार के अवृद्धिकारी संघटक का पूर्व-निर्दिष्ट प्रतिशत होगा और वह मानकीय उपलब्धता से अधिक संयंत्र की उपलब्धता पर आधारित होगा। लागू प्रतिशत आरएफपी में निर्दिष्ट किया जाएगा और वह क्षमता प्रभार के अवृद्धिकारी संघटक के 40% तक सीमित होगा। मामला-2 किस्म (पैरा 2.2 के संदर्भ में) की अधिप्राप्ति के लिए अधिप्राप्तिकर्ता को मानकीय उपलब्धता से अधिक उत्पादित ऊर्जा पर अस्वीकृति का पहला अधिकार होगा। अगर वास्तविक उपलब्धता मानकीय उपलब्धता से कम है तो क्षमता प्रभार उपलब्धता की तुलना में कमी के लिए देय होगा। ऐसे मामले में उपलब्धता में कमी की सीमा तक क्षमता प्रभार के 20% की दर पर दण्ड लागू होगा।

- 4.6 बिक्रेता (सफल बोलीदाता) समय-समय पर भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) में यथानिर्दिष्ट समय-निर्धारण कार्यविधि के अनुसार दैनिक आधार पर उपलब्धता घोषित करेगा। इसके अतिरिक्त, बिक्रेता और अधिप्राप्तिकर्ता आईईजीसी के सभी संगत प्रावधानों का पालन करेंगे। अगर अधिप्राप्तिकर्ता घोषित उपलब्धता तक उत्पादन प्राप्त नहीं करता तो उसे बिक्रेता द्वारा बाजार में बेचा जा सकता है और परिवर्ती प्रभारों के आधिक्य में बिक्री से हुई प्राप्ति की अधिप्राप्तिकर्ता के साथ बराबर-बराबर भागीदारी की जाएगी।
- 4.7 बोली प्रस्तुत करने की तारीख को लागू कानून के संबंध में उसमें किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पादन अथवा विद्युत की बिक्री पर कर में हुए किसी परिवर्तन को अलग से समायोजित किया जाएगा।
- 4.8 किसी वर्ष के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्षमता प्रभार का अनुपात संविदा की अवधि के दौरान अत्यधिक फ्रंट-लोडिंग अथवा बैक-लोडिंग से बचने के लिए 0.7 से कम नहीं होगा।
- 4.9 अगर पीक-लोड अथवा मौसमी आवश्यकता बेस-लोड की आवश्यकता से स्पष्ट है तो बोलीदाता ऐसे पीक-लोड अथवा मौसमी आपूर्ति के लिए स्पष्ट मूल्य इंगित करेंगे, जिसे अलग-अलग मूल्यांकित किया जाएगा। बेस और पीक/मौसमी लोड के लिए विद्युत के एक ही स्रोत के लिए बताई गई विभेदक दरें दिशानिर्देश का उल्लंघन अथवा अनुचित कार्य नहीं होगी।
- 4.10 बोलीदाताओं को पर्याप्त भुगतान सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। भुगतान सुरक्षा में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं
- (i) साख पत्र
 - (ii) विश्वसनीय एस्करो कार्यतंत्र द्वारा समर्थित साख पत्र

अगर बिक्रेता भुगतान चक्र के अनुसार नियत तारीख तक अधिप्राप्तिकर्ता से पूरा भुगतान वसूल नहीं करता तो बिक्रेता 7 दिनों के बाद कमी की सीमा तक साख पत्र के नकदीकरण द्वारा भुगतान सुरक्षा कार्यतंत्र अथवा एस्करो कार्यतंत्र का आश्रय ले सकता है। अधिप्राप्तिकर्ता भुगतान की अगली तारीख के पूर्व भुगतान सुरक्षा कार्यतंत्र अथवा एस्करो कार्यतंत्र का आश्रय ले सकता है। अधिप्राप्तिकर्ता भुगतान की अगली तारीख के पूर्व भुगतान सुरक्षा कार्यतंत्र बहाल करेगा। भुगतान सुरक्षा कार्यतंत्र के बावजूद भी भुगतान प्राप्त करने में विफलता भुगतान चूक होगी। भुगतान चूक की दशा में बिक्रेता 7 दिनों की नोटिस देने के बाद अधिप्राप्तिकर्ता से देय क्षमता प्रभार पर दावा खोए बिना संविदाकृत विद्युत के 25% की बिक्री अन्य पार्टियों को कर सकता है। अगर भुगतान सुरक्षा कार्यतंत्र भुगतान चूक होने के 30 दिनों के भीतर पूर्णतः बहाल नहीं किया जाता तो बिक्रेता अधिप्राप्तिकर्ता से देय क्षमता प्रभार पर दावा खोए बिना संविदाकृत पूर्ण

विद्युत की बिक्री अन्य पार्टियों को कर सकता है। ऐसी पार्टियों को बिक्री से वसूल ऊर्जा प्रभारों के अधिशेष को अधिप्राप्तिकर्ता की क्षमता प्रभार देयता के बदले समायोजित किया जाएगा। अगर ऊर्जा प्रभारों की तुलना में आधिक्य अधिप्राप्तिकर्ता की क्षमता देयता से अधिक है तो क्षमता प्रभार देयता की तुलना में ऐसा आधिक्य बिक्रेता द्वारा रखा जाएगा।

ऊर्जा प्रभार

- 4.11 जहां लागू हो, संविदा के प्रचालन के दौरान देय ऊर्जा प्रभार वृद्धि के उपयुक्त प्रावधान के साथ बोली में निर्दिष्ट आधार ऊर्जा प्रभारों पर संबद्ध होगा। अगर बोलीदाता संविदा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित ऊर्जा प्रभार दरें प्रदान करता है तो उसकी टैरिफ में अनुमति दी जाएगी। अन्य मामलों में ऊर्जा प्रभार बोली के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त ईंधन वृद्धि सूचकांक के अनुसार देय होगा। निवल उष्मा दर पर आधारित बोलियों के मामले में ईंधन का मूल्य पैरा 4.2 के अधीन यथानिर्दिष्ट माना जाएगा। तथापि, यह ईंधन वृद्धि देश में उत्पादित ईंधन के मामले में सरकार के प्रशासित मूल्य कार्यतंत्र अथवा स्वतंत्र विनियामक मूल्य नियतन के अधीन होगी। विभिन्न ईंधनों के लिए लागू सूचकांकों को आरएफपी दस्तावेज में अभिज्ञात किया जाएगा।
- 4.12 उत्पादन स्टेशनों के उष्मा दर के निम्नीकरण के लिए कोई समायोजन प्रदान नहीं किया जाएगा। यहां तक कि निवल उष्मा दर पर आधारित बोलियों के मामले में बोलीदाता कार्यस्थल दशा, लोडिंग दशा और आवृत्ति परिवर्तन आदि को शामिल करेगा और संविदा की अवधि के लिए बताई गई निवल उष्मा दर पर कोई समायोजन की अनुमति नहीं होगी।
- 4.13 अगर कोई बोलीदाता **मामला 1** के अधीन जल विद्युत का प्रस्ताव करता है, ~~अर्थात्~~ अधिप्राप्तिकर्ता **मामला 2** के अधीन जल विद्युत की बोलियां आमंत्रित करता है तो जलवैज्ञानिक जोखिम का वहन अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी परियोजना के लिए जलवैज्ञानिक आंकड़ा प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हों और वह पहले से ही पार्टियों को ज्ञात हो। डिजाइन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उपलब्धता का परिणाम होने वाला जलवैज्ञानिक लाभ किसी प्रभार के बिना अधिप्राप्तिकर्ता को प्रदान किया जाएगा। जल विद्युत परियोजना के लिए भूवैज्ञानिक जोखिम का वहन प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा।
- 4.14 ऊर्जा प्रभार अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा अनुसूचित ऊर्जा के लिए बिक्रेता को देय होगा। सहमत्य ऊर्जा अनुसूची के बाद विपणन को एबीटी/यूआई कार्यतंत्र के अधीन निपटारा जाएगा।

संयुक्त क्षमता और ऊर्जा प्रभार

- 4.15 वैसे मामलों, जहां अधिप्राप्ति प्रक्रिया बोलीदाता को संयुक्त क्षमता और ऊर्जा प्रभार प्रस्तुत करने की अनुमति देती है वहां प्रस्तावित प्रभार विद्युत क्रय करार (पीपीए) की अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित रहेगा और मूल्य बोली में बिक्रेता द्वारा प्रस्तावित दरों से अधिक टैरिफ की वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4.16 बोलीदाता वार्षिक आधार पर परियोजना से मानकीय उपलब्धता निर्दिष्ट करेगा। आरएफक्यू/आरएफपी चरण पर बोलीदाताओं को उपलब्ध कराया गया मॉडल विद्युत क्रय करार (पीपीए) में बिक्रेता द्वारा मानकीय उपलब्धता की पूर्ति नहीं करने की दशा में दंड का उपयुक्त प्रावधान होगा। आरएफक्यू/आरएफपी में ऐसे स्टेशनों से अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम ऑफटेक की शर्तें भी निर्दिष्ट होंगी।
- 4.17 मानकीय स्तर से अधिक अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा ऑफटेक के लिए बिक्रेता द्वारा देय प्रति कि.वा.घं. दरें वहीं होंगी जो मानकीय उपलब्धता तक लागू दरें होती हैं। अगर अधिप्राप्तिकर्ता संविदा के अनुसार बिक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई ऊर्जा अनुसूचित नहीं करता तो बिक्रेता अन्य पार्टियों की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगा। बिक्रेता से तीसरी पार्टियों को ऐसी बिक्री के लिए अधिप्राप्तिकर्ता को कोई भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

5. बोली देने की प्रक्रिया

दो-चरण वाली प्रक्रिया

- 5.1 इन दिशानिर्देशों के अधीन दीर्घावधिक अधिप्राप्ति के लिए इन दिशानिर्देशों के अधीन बोली प्रक्रिया के लिए पृथक अर्हता के अनुरोध (आरएफक्यू) और प्रस्ताव के अनुरोध (आरएफपी) चरणों वाली दो चरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अधिप्राप्तिकर्ता अपने विकल्प पर आरएफपी और आरएफक्यू प्रक्रियाओं को संयोजित करते हुए मध्यावधिक अधिप्राप्ति के लिए एकल चरण निविदा अपना सकता है। अधिप्राप्तिकर्ता अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि इन दिशानिर्देशों और मानक बोली दस्तावेजों के अनुरूप आरएफक्यू और आरएफपी सहित बोली दस्तावेज तैयार करेंगे।
- 5.2 अधिप्राप्तिकर्ता कम से कम दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों, कंपनी की वेबसाइट और अधिमानतः व्यापार पत्रिकाओं में व्यापक प्रचार के लिए आरएफक्यू नोटिस प्रकाशित करेगा। बोली देना आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली देने द्वारा होगा। आरएफक्यू जारी करने के प्रयोजनार्थ बोलीदाता द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम शर्तें आरएफक्यू नोटिस में अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी।

- 5.3 अधिप्राप्तकर्ता किसी भी बोलीदाता/भाग लेने वाले को निविदा दस्तावेज की केवल लिखित व्याख्या प्रदान करेगा और वह अन्य सभी बोलीदाता को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी पार्टियां बोलीदाताओं से लिखित सूचना और स्वीकृतियों पर ही निर्भर करेंगी।
- 5.4 आरएफक्यू में अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले मानक प्रलेखीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे;
- खरीदे जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मेगावाट में मात्रा। बोलीदाताओं को नमनीयता प्रदान करने के लिए इसे एक सीमा के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसके भीतर बोलियां स्वीकार की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, अधिप्राप्तिकर्ता बोलीदाताओं को दी गई न्यूनतम मात्रा के अधीन निविदाकृत मात्रा के भाग के लिए बोली देने हेतु नमनीयता भी प्रदान कर सकता है।
 - अधिप्राप्तिकर्ता एक ही बोली प्रक्रिया के माध्यम से स्पष्ट बेस-लोड आवश्यकता और पीक-लोड आवश्यकता अलग-अलग निर्दिष्ट कर सकता है। मौसमी विद्युत आवश्यकता, अगर कोई हो, भी निर्दिष्ट की जाएगी।
 - प्रस्तावित संविदा की अवधि; (जहां तक संभव हो, दीर्घावधिक अधिप्राप्ति के मामले में परियोजना की अवधि के अनुरूप संविदा करना उचित है)। बोलीदाता से उसके द्वारा प्रस्तावित ईंधन पर निर्भर करते हुए परियोजना की प्रत्याशित अवधि के लिए टैरिफ संरचना बताने की अपेक्षा होगी। परियोजना की प्रत्याशित अवधि गैस/द्रव ईंधन आधारित परियोजनाओं के लिए 15 वर्ष, कोयला-आधारित परियोजनाओं के लिए 25 वर्ष और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 35 वर्ष अनुमानित है।
 - बिक्रेता द्वारा पूरी की जाने वाली मानकीय उपलब्धता आवश्यकता (पीक और ऑफ-पीक घंटों के लिए अलग-अलग, अगर आवश्यक हो)।
 - पीक और ऑफ-पीक घंटों की परिभाषा।
 - आपूर्ति प्रारंभ करने की प्रत्याशित तारीख।
 - स्थल, जहां विद्युत की सुपुर्दगी की जानी है।
 - जहां भी लागू हों, अधिप्राप्तिकर्ता बोलीदाताओं से निर्दिष्ट किए जाने वाले निर्माण मानदंडों की उपेक्षा कर सकता है।
 - संलग्न बोली दस्तावेजों में यथा रेखांकित आवश्यक साक्ष्य के साथ न्यूनतम निवल मूल्य, राजस्व आदि सहित बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली द्वितीय आवश्यकता।

(ii) विद्युत के बिक्रेता के साथ किए जाने के लिए प्रस्तावित मॉडल विद्युत क्रय करार

विद्युत क्रय करार में निम्नलिखित पर आवश्यक ब्यौरा शामिल होगा:

- पार्टियों के बीच जोखिम आवंटन
- न्यूनतम लोड दशाओं पर तकनीकी आवश्यकताएं
- आश्वस्त ऑफटेक स्तर
- उद्योग मानकों के अनुसार दैवी विपत्तियों का खण्ड
- विद्युत के समय-निर्धारण के लिए शीर्ष अवधि
- चूक की शर्त और उसका उपचार तथा दंड;
- अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली भुगतान सुरक्षा

(iii) बोलीदाता के प्रस्ताव की वैधता अवधि:

- (iv) विद्युत क्रय करार (पीपीए) की अवधि की समाप्ति पर चयनित बोलीदाता (अगर कोई हो) द्वारा परिसंपत्तियों के अधिप्राप्तिकर्ता को स्थानान्तरण की आवश्यकता।
- (v) आईईजीसी के प्रावधानों/राज्य ग्रिड संहिता, उपयुक्त आयोग के संगत आदेश (अर्थात् वि.वि.आ. का उपलब्धता आधारित टैरिफ आदेश) रिसर्जन मानदंड आदि, जैसा लागू हो, सहित बोलीदाता द्वारा पूरा किए जाने वाले अन्य तकनीकी, प्रचालनात्मक और सुरक्षा मानदंड।
- (vi) अधिप्राप्तिकर्ता अपने विकल्प पर बोली की प्रस्तुति के समय ऋणदाताओं से वित्तीय प्रतिबद्धता के प्रदर्शन की अपेक्षा कर सकता है। यह वित्तीय समापन और विद्युत की सुपुर्दगी की प्रक्रिया तेज करेगा।
- (vii) अधिप्राप्तिकर्ता और आपूर्तिकर्ता इन शर्तों के अधीन कि नए भागीदार आरएफपी की सभी शर्तें पूरी करते हैं, छोड़ने के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

5.5 आरएफपी उन सभी बोलीदाताओं को जारी की जाएगी, जिन्होंने आरएफक्यू चरण पर अर्हता प्राप्त की है। अगर बोलीदाता कोई विपथन चाहता है और अधिप्राप्तिकर्ता यह पाता है कि विपथन उचित है तो अधिप्राप्तिकर्ता विपथन पर सहमत होने के पूर्व उपयुक्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा। स्पष्टीकरण/संशोधित बोली दस्तावेज उन सभी को वितरित किया जाएगा, जिन्होंने विपथन और स्पष्टीकरण के बारे में सूचित करते हुए आरएफक्यू दस्तावेज मांगा था। जहां भी संशोधित बोली दस्तावेज जारी किए जाते हैं अधिप्राप्तिकर्ता बोलियां प्रस्तुत करने के लिए ऐसे दस्तावेज जारी करने के बाद बोलीदाताओं को कम से कम दो महीना प्रदान करेगा।

5.6 आरएफपी में अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले मानक प्रलेखीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे;

- (i) बोलीदाताओं द्वारा वर्णन किए जाने वाले टैरिफ की संरचना;
- (ii) चयनित बोलीदाता के साथ किया जाने वाला प्रस्तावित विद्युत क्रय करार (पीपीए)।
आरएफक्यू चरण में प्रस्तावित मॉडल विद्युत क्रय करार (पीपीए) को दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संशोधित किया जा सकता है और उसे आरएफपी का प्रत्युत्तर देने वाली सभी पार्टियों को प्रदान किया जाएगा। आरएफपी चरण के बाद कोई और संशोधन नहीं किया जाएगा;
- (iii) अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भुगतान सुरक्षा।
आरएफक्यू चरण में इंगित भुगतान सुरक्षा आरएफक्यू चरण में प्राप्त पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी के आधार पर संशोधित की जा सकती है। तथापि, आरएफपी चरण के बाद भुगतान सुरक्षा में और कोई संशोधन अनुमेय नहीं होगा।
- (iv) बोलियों के मूल्यांकन के लिए छूट दर सहित अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा अपनाई जाने वाली बोली-मूल्यांकन विधि।
बोलियों का मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा बताए गए टैरिफ के क्षमता और ऊर्जा संघटनों को संयोजित करते हुए मिश्रित संतुलित टैरिफ के लिए किया जाएगा। बेस लोड, पीक लोड और मौसमी विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए मिश्रित पूछताछ के मामले में प्रत्येक किस्म की आवश्यकता के लिए अलग-अलग बोली का मूल्यांकन किया जाएगा। टैरिफ के क्षमता संघटक में पृथक अवृद्धिकारी (नियत) और वृद्धिकारी (सूचकांकित) संघटक हो सकते हैं। वृद्धिकारी संघटक की वृद्धि के लिए अपनाया जाने वाला सूचकांक आरएफपी में निर्दिष्ट किया जाएगा। बोली के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कोयले के लिए पिछले 30 वर्षों और गैस/एलएनजी के लिए 15 वर्षों (केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नीचे (vi) में अधिसूचना के अनुसार) हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संगत ईंधन सूचकांक की मध्यमान वृद्धि दर का प्रयोग बोलीदाता द्वारा बताए गए ऊर्जा प्रभार में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा। तथापि, यह उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां बोलीदाता प्रस्तावित आपूर्ति के प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित ऊर्जा प्रभार बताता है और ऐसे मामले में बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा प्रभार बोली मूल्यांकन के लिए अपनाया जाएगा। संतुलित टैरिफ के संगणन के लिए नियत और परिवर्ती प्रभारों के संयोजन को छूट देने की दर 10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूतियों के लिए विद्यमान दर होगी।
- (v) आरएफपी अधिकतम अवधि-प्रदान करेगा, जिसके भीतर चयनित बोलीदाता को अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा चयनित बोलीदाता के साथ विद्युत क्रय करार करने के बाद अधिप्राप्तिकर्ता के दायित्वों की पूर्ति करने के अधीन आपूर्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए।

अगर आपूर्ति दीर्घावधिक अधिप्राप्ति के लिए मांगी जाती है तो यह साधारणतया चयनित बोलीदाता के साथ विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से चार वर्ष से कम नहीं होगी। आरएफपी निर्णीत हर्जाने, जो आपूर्ति में विलम्ब की दशा में लागू होगा, भी निर्दिष्ट करेगा।

- (vi) बोली के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक छः महीने पर निम्नलिखित अधिसूचित और अद्यतन किया जाएगा:

1. लागू छूट दर
2. कोयले के लिए वृद्धि दर
3. गैस/एलएनजी के लिए वृद्धि दर
4. सूचकांकित क्षमता प्रभार संघटक पर लागू की जाने वाली मुद्रास्फीति दर।

बोली प्रस्तुत करना और मूल्यांकन

- 5.7 प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए अर्हक बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या अधिप्राप्तिकर्ता की संबद्ध कंपनी अथवा कंपनियों के अतिरिक्त कम से कम दो होनी चाहिए। अगर आरएफक्यू/आरएफपी का प्रत्युत्तर देने वाले अर्हक बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है और अधिप्राप्तिकर्ता फिर भी बोली देने की प्रक्रिया जारी रखना चाहता है तो उसे उपयुक्त आयोग की सहमति से किया जा सकता है।
- 5.8 बोलीदाताओं द्वारा परिसंघ का निर्माण अनुमत्य होगा। ऐसे मामलों में परिसंघ शीर्ष सदस्य को अभिज्ञात करेगा और बोली प्रक्रिया के लिए सभी पत्राचार शीर्ष सदस्य के माध्यम से किया जाएगा। अधिप्राप्तिकर्ता अगर आवश्यक हो परिसंघ के शीर्ष सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड और लॉक-इन आवश्यकताएं निर्दिष्ट कर सकता है।
- 5.9 अधिप्राप्तिकर्ता बोलियों के मूल्यांकन के लिए अधिप्राप्तिकर्ता के संगठन और संबद्ध से बाहर के कम से कम एक सदस्य के साथ एक समिति गठित करेगा। बाहरी सदस्यों को वित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञता होगी। अधिप्राप्तिकर्ता बाहरी सदस्य से सीधे अथवा अपने संबद्ध के माध्यम से पूर्व संबंधों का खुलासा करेगा, जो संभावित संघर्ष सृजित कर सकता है।
- 5.10 पात्र बोलीदाताओं से पृथक् तकनीकी और मूल्य बोलियां प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। बोलीदाताओं से बोलियों के साथ आवश्यक बोली गारंटी भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। अगंभीर बोलियों को हटाने के लिए पर्याप्त और उचित बोली-गारंटी मांगी जाएगी। बोलियां सार्वजनिक रूप से खोली जाएंगी और भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।

- 5.11 तकनीकी बोलियां यह सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त की जाएंगी कि प्रस्तुत बोलियां सभी तकनीकी मूल्यांकन पैरामीटरों पर आरएफपी दस्तावेज में निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करती हैं। केवल वही बोलियां, जो आरएफपी में निर्धारित न्यूनतम तकनीकी मानदंड पूरा करती हैं, पर मूल्य बोलियों पर आगे मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।
- 5.12 मूल्य बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी अगर उसमें मूल्य बोली की प्रस्तुति के लिए निविदा शर्तों से कोई विपथन विहित होता है।
- 5.13 जहां भी लागू हो, मूल्य बोली आरएफपी की शर्तों के अनुसार चयनित बोलीदाता द्वारा परिसंपत्तियों के स्थानान्तरण के लिए अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा देय सीमांत मूल्य भी निर्दिष्ट करेगी।
- 5.14 बोलीदाता उत्पादन स्टेशन बस-बार अथवा राज्य पारेषण नेटवर्क के अंतरापृष्ठ स्थल में विद्युत का मूल्य (सहायक उपकरणों को घटाकर) बता सकता है। बोली मूल्यांकन में मानकीकरण के प्रयोजनार्थ टैरिफ की तुलना उत्पादक/आपूर्तिकर्ता के अंतरापृष्ठ स्थल पर राज्य पारेषण नेटवर्क के साथ की जाएगी। अगर बोलीदाता उत्पादन स्टेशन बस-बार पर अपनी दर बताता है तो कें.वि.वि.आ. के विद्यमान आदेशों के आधार पर क्षेत्रीय/ अंतःक्षेत्रीय नेटवर्क के लिए मानकीय पारेषण प्रभार, अगर लागू हों, प्रस्तुत की गई मूल्य बोली में जोड़ा जाएगा। राज्य पारेषण नेटवर्क के लिए प्रभार अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा देय होगा और वह मूल्यांकन मानदंड का हिस्सा नहीं होगा।
- 5.15 बोलीदाता, जिसने मूल्यांकन कार्यविधि के अनुसार निम्नतम संतुलित टैरिफ बताया है, पर ठेके के लिए विचार किया जाएगा। मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य बोलियां अस्वीकृत करने का अधिकार होगा अगर बताई गई दरें विद्यमान बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं।

दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विपथन

- 5.16 अगर इन दिशानिर्देशों से कोई विपथन हो तो वह उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा। उपयुक्त आयोग 90 दिनों से अनधिक उचित समय के भीतर बोली दस्तावेजों को अनुमोदित करेगा अथवा संशोधन की अपेक्षा करेगा।

विवाचन

5.17 अधिप्राप्तिकर्ता भारतीय विवाचन और समाधान अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार एक सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान (एडीआर) कार्यतंत्र स्थापित करेगा। एडीआर बोली प्रक्रिया और उसके प्रलेखीकरण से संबंधित विवाद कम करने के लिए अनिवार्य और समयबद्ध होगा।

अगर एडीआर विवाद का समाधान करने में विफल रहता है तो वह विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी

5.18 बोली प्रक्रिया के लिए एक सुझाव दी गई समय-सारणी नीचे इंगित की गई है। अधिप्राप्तिकर्ता विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर यहां इसमें इंगित विस्तारित समय-सीमा दे सकता है और ऐसे परिवर्तन को इन दिशानिर्देशों से विपथन नहीं माना जाएगा।

घटना	प्रारंभ तारीख से बीता हुआ समय
आरएफक्यू का प्रकाशन	प्रारंभ तारीख
आरएफक्यू के प्रत्युत्तर की प्रस्तुति	60 दिन
प्रत्युत्तर के आधार पर सूची बनाना और आरएफपी जारी करना	90 दिन
बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन आदि	150 दिन
अंतिम स्पष्टीकरण और आरएफपी का संशोधन	180 दिन
तकनीकी और मूल्य बोली की प्रस्तुति	360 दिन
बोलीदाताओं की सूची बनाना और आशय-पत्र जारी करना	390 दिन
करार पर हस्ताक्षर करना	425 दिन

5.19 एकल चरण बोली प्रक्रिया के लिए सुझाव दी गई समय-सारणी नीचे इंगित की गई है। अधिप्राप्तिकर्ता विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर यहां इसमें इंगित विस्तारित समय-सीमा दे सकता है और ऐसे परिवर्तन को इन दिशानिर्देशों से विपथन नहीं माना जाएगा।

घटना	प्रारंभ तारीख से बीता हुआ समय
आरएफक्यू का प्रकाशन	प्रारंभ तारीख
बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन आदि और आरएफपी का संशोधन	90 दिन
तकनीकी और मूल्य बोली की प्रस्तुति	180 दिन
बोलीदाताओं की सूची बनाना और आशय-पत्र जारी करना	210 दिन
करार पर हस्ताक्षर करना	240 दिन

6. ठेका देना और निष्कर्ष

- 6.1 आरएफपी चरण के पूर्व बोली दस्तावेज में अंतिम रूप दी गई शर्तों के अनुसार चयन प्रक्रिया के फलस्वरूप चयनित बोलीदाता के साथ विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
- 6.2 पार्टियों के बीच विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप मूल्यांकन समिति इन दिशानिर्देशों के अनुपालन और अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा स्थापित बोली प्रक्रिया पर उपयुक्त प्रमाणीकरण प्रदान करेगी।
- 6.3 अधिप्राप्तिकर्ता बोली जीतने की शर्तें और अन्य सभी बोलियों की गुमनाम तुलना इंगित करके बोली के मूल्यांकन को सार्वजनिक करेगा। अधिप्राप्तिकर्ता सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित सभी संविदाओं को भी सार्वजनिक करेगा।
- 6.4 मूल्यांकन समिति द्वारा प्रमाणीकरण के साथ अंतिम विद्युत क्रय करार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार टैरिफ अपनाने के लिए उपयुक्त आयोग को अग्रेषित किया जाएगा।

अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER**RESOLUTION**

New Delhi, the 19th January, 2005

**No. 23/11/2004-R & R (Vol. II).—Guidelines for Determination of Tariff by Bidding
Process for Procurement of Power by Distribution Licensees**

1. Preamble

Promotion of competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 (the Act). Power purchase costs constitute the largest cost element for distribution licensees. Competitive procurement of electricity by the distribution licensees is expected to reduce the overall cost of procurement of power and facilitate development of power markets. Internationally, competition in wholesale electricity markets has led to reduction in prices of electricity and in significant benefits for consumers.

Section 61 & 62 of the Act provide for tariff regulation and determination of tariff of generation, transmission, wheeling and retail sale of electricity by the Appropriate Commission. Section 63 of the Act states that –

“Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government.”

These guidelines have been framed under the above provisions of section 63 of the Act. The specific objectives of these guidelines are as follows:

1. Promote competitive procurement of electricity by distribution licensees;
2. Facilitate transparency and fairness in procurement processes;
3. Facilitate reduction of information asymmetries for various bidders;

4. Protect consumer interests by facilitating competitive conditions in procurement of electricity;
5. Enhance standardization and reduce ambiguity and hence time for materialization of projects;
6. Provide flexibility to suppliers on internal operations while ensuring certainty on availability of power and tariffs for buyers.

2. Scope of the Guidelines

2.1. These guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of electricity by distribution licensees (Procurer) for:

- (a) long-term procurement of electricity for a period of 7 years and above;
- (b) Medium term procurement for a period of upto 7 years but exceeding 1 year.

2.2. The guidelines shall apply for procurement of base-load, peak-load and seasonal power requirements through competitive bidding, through the following mechanisms:

- (i) Where the location, technology, or fuel is not specified by the procurer (**Case 1**);
- (ii) For hydro-power projects, load center projects or other location specific projects with specific fuel allocation such as captive mines available, which the procurer intends to set up under tariff based bidding process (**Case 2**).

2.3. Unless explicitly specified in these guidelines, the provisions of these guidelines shall be binding on the procurer. The process to be adopted in event of any deviation proposed from these guidelines is specified later in these guidelines under para 5.16.

2.4. Procurement by more than one distribution licensee through a combined bid process shall be permitted. For such combined procurement, each procurer shall provide the necessary information required as per these guidelines. To ensure standardization in evaluation of bids, the payment security and other commercial terms offered to the bidders by the various procurers shall not vary. The price offered by the bidders shall also be the same for the distribution licensees inviting the bid.

2.5. All obligations on part of the procurers for the bid process shall be considered to be met only when each and every procurer meets such obligations set out in the Request for Proposal (RFP). This shall, however, not preclude the bidder from waiving such stipulation if the bidder finds it reasonable to do so, and the same shall not be construed to be violation of these guidelines.

3. Preparation for inviting bids

3.1. To expedite the bid process, the following conditions shall be met by the procurer:

- (i) The bid documentation shall be prepared in accordance with these guidelines and the approval of the appropriate Regulatory Commission shall be obtained unless the bid documents are as per the standard bid documents issued by the Central Government. In such cases, an intimation shall be sent by the procurer to the appropriate Regulatory Commission about initiation of the bidding process.
- (ii) Approval of the Appropriate Commission shall be sought in event of the deviations from the bidding conditions contained in these guidelines, following the process described in para 5.16 of these guidelines.
- (iii) Approval of the Appropriate Commission shall be sought prior to initiating the bidding process in respect of the following aspects:
 - (a) For the quantum of capacity / energy to be procured, in case the same is exceeding the projected additional demand forecast for next three years (Both for Case 1 and Case 2).
 - (b) For the transfer price of fuel, in case of fuel specific procurement enquiry, if such price has not been determined by government, government approved mechanism or a fuel regulator (under Case 2).

3.2. For long-term procurement from hydro electric projects or for projects for which pre-identified sites are to be utilized (Case 2), the following activities should be completed by the procurer, or authorized representative of the procurer, before commencing the bid process:

- Site identification and land acquisition required for the project
- Environmental clearance
- Fuel linkage, if required (may also be asked from bidder)
- Water linkage
- Requisite Hydrological, geological, meteorological and seismological data necessary for preparation of Detailed Project Report (DPR), where applicable.

The bidder shall be free to verify geological data through his own sources, as the geological risk would lie with the project developer.

The project site shall be transferred to the successful bidder at a declared price.

3.3. It is recommended that the procurer should obtain the transmission clearances necessary for receiving power at the delivery points prior to inviting bids. However this shall not be a binding condition for the bid process. Unless

otherwise specified in the bid documents, it shall be the responsibility of the selected bidder to obtain transmission linkage for evacuation and inter-State transmission of power (where applicable).

4. Tariff Structure

- 4.1. For procurement of electricity under these guidelines, tariff shall be paid and settled for each payment period (not exceeding one month). A multi-part tariff structure featuring separate capacity and energy components of tariff shall ordinarily form the basis for bidding. However, for medium term procurement the procurer may, at his option, permit bids on a single part basis, and the same shall be clearly specified in the Request for Qualification (RFQ) / Request for Proposal (RFP).
- 4.2. In case of long term procurement with specific fuel allocation (Case 2), the procurer shall invite bids on the basis of capacity charge and net quoted heat rate. The net heat rate shall be ex-bus taking into account internal power consumption of the power station. The energy charges shall be payable as per the following formula :

$$\text{Energy Charges} = \frac{\text{New quoted heat rate} \times \text{Scheduled Generation} \times \text{Monthly Weighted Average Price of Fuel}}{\text{Monthly Average Gross Calorific Value of Fuel.}}$$

If the price of the fuel has not been determined by the Government of India, government approved mechanism or the Fuel Regulator, the same shall have to be approved by the appropriate Regulatory Commission.

In case of coal / lignite fuel, the cost of secondary fuel oil shall be factored in the capacity charges.

- 4.3. Tariffs shall be designated in Indian Rupees only. Foreign exchange risks, if any, shall be borne by the supplier. Transmission charges in all cases shall be borne by the procurer.

Capacity charges

- 4.4. Capacity charge shall be paid based on actual availability in kwh, as per charges quoted in Rs/kwh and shall be limited to the normative availability (or normative capacity index for hydro electric stations). The normative availability shall be aligned to the level specified in the tariff regulations of the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) prevailing at the time of the bid process, and shall be computed on annual basis. The capacity component of tariffs may feature separate non-escalable (fixed) and escalable (indexed) components. The indices to be adopted for escalation of the escalable component shall only be

Wholesale Price Index (WPI) or Consumer Price Index (CPI) and the Base year shall be specified in the bid document.

- 4.5. Capacity charges for supply beyond the normative availability shall be a pre-specified percentage of the non-escalable component of the capacity charges, and shall be based on the availability of the plant beyond the normative availability. The percentage applicable shall be specified in the RFP, and shall be limited to a 40% of the non-escalable component of the capacity charges. For procurement of Case-2 type (in reference to para 2.2.), the procurer shall have first right of refusal on energy generated beyond normative availability. In case actual availability is less than the normative availability, capacity charges shall not be payable for the shortfall compared to the normative availability. In such case a penalty at the rate of 20% of the capacity charge shall be applicable to the extent of the shortfall in availability.
- 4.6. The seller (successful bidder) shall declare availability on a daily basis in accordance with the scheduling procedure as stipulated in the Indian Electricity Grid Code (IEGC) from time to time. Further the seller and procurer shall comply with all relevant provisions of the IEGC. If the procurer does not avail generation up to declared availability, the same can be sold in market by the seller, and sale realization in excess of variable charges shall be equally shared with the procurer.
- 4.7. Any change in tax on generation or sale of electricity as a result of any change in Law with respect to that applicable on the date of bid submission shall be adjusted separately.
- 4.8. Ratio of minimum and maximum capacity charge for any year shall not be less than 0.7 to avoid excessive front loading or back loading during the period of contract.
- 4.9. In case peakload or seasonal requirements are distinct from baseload requirements, the bidders shall indicate distinct prices for such peakload or seasonal supply which shall be evaluated separately. Differential rates quoted for the same source of power for base and peak/seasonal load shall not constitute violation of guideline or unfair practice.
- 4.10. Adequate payment security shall be made available to the bidders. The payment security may constitute:
 - (i) Letter of Credit (LC)
 - (ii) Letter of Credit (LC) backed by credible escrow mechanism.

In the case the seller does not realize full payment from the procurer by the due date as per payment cycle, the seller may after 7 days, take recourse to payment security mechanism by encashing the LC to the extent of short fall or take recourse to escrow mechanism. The procurer shall restore the payment security mechanism prior to the next date of payment. Failure to realize payment even through payment security mechanism shall constitute an event of payment default. In the event of payment default the seller, after giving 7 days notice, can sell up to

25% of the contracted power to other parties without losing claim on the capacity charges due from the procurer. If the payment security mechanism is not fully restored within 30 days of the event of the payment default, the seller can sell full contracted power to other parties without losing claim on the capacity charges due from the procurer. The surplus over energy charges recovered from sale to such other parties shall be adjusted against the capacity charge liability of the procurer. In case the surplus over energy charges is higher than the capacity charge liability of the procurer, such excess over the capacity charge liability shall be retained by the seller.

Energy Charges

- 4.11. Where applicable, the energy charges payable during the operation of the contract shall be related on the base energy charges specified in the bid with suitable provision for escalation. In case the bidder provides firm energy charge rates for each of the years of the contract term, the same shall be permitted in the tariffs. In other cases, the energy charges shall be payable in accordance with fuel escalation index used for evaluation of the bid. In case of bids based on net heat rate, the price of fuel shall be taken as stipulated under para 4.2. However, the fuel escalation will be subject to any administered price mechanism of Government or independent regulatory price fixation in case of fuel produced within the country. The applicable indices for various fuels shall be identified in the RFP documents.
- 4.12. No adjustment shall be provided for heat rate degradation of the generating stations. Even in case of bids based on net heat rate, the bidder shall factor in site conditions, loading conditions, frequency variations etc and no adjustment shall be allowed on the quoted net heat rate for the duration of the contract.
- 4.13. In case a bidder offers hydro power, under **Case 1** or the procurer invites bids of hydro power under **Case 2**, the hydrological risk shall be borne by the Procurer, provided the hydrological data of such a project is based on authentic sources and is known to the parties in advance. Any hydrological advantages resulting in energy availability beyond the design energy shall be passed on to the Procurer without any charge. The geological risk for the hydro project shall be borne by the developer.
- 4.14. Energy charges shall be payable by the procurer to the seller for the scheduled energy. Deviations beyond agreed energy schedules shall be settled under the ABT/UI mechanism.

Combined capacity and energy charges

- 4.15. In cases where the procurement process permits bidders to submit combined capacity and energy charges, the charges proposed shall be firm for each of the years of the term of the Power Purchase Agreement (PPA), and no

escalation of tariffs shall be permitted over and above the rates proposed by the seller in the price bid.

- 4.16. The bidder shall specify the normative availability from the project on an annual basis. The model PPA made available to the bidders at the RFQ/RFP stage shall feature appropriate provisions for penalties in event of the normative availability not being met by the seller. The RFQ/RFP shall also specify minimum offtake conditions for procurement from such stations.
- 4.17. The per kwh rates payable to the seller for offtake by the procurer over and above the normative levels shall be the same as the rates applicable till normative availability. In case the procurer does not schedule the energy made available by the seller as per the contract, the seller shall be free to sell to other parties. The seller shall not be required to make any payments to the procurer for such sales to third parties.

5. Bidding Process

Two-stage process

- 5.1. For long-term procurement under these guidelines, a two-stage process featuring separate Request for Qualification (RFQ) and Request for Proposal (RFP) stages shall be adopted for the bid process under these guidelines. The procurer may, at his option, adopt a single stage tender process for medium term procurement, combining the RFP and RFQ processes. Procurer or authorized representative shall prepare bid documents including the RFQ and RFP in line with these guidelines and standard bid documents.
- 5.2. The procurer shall publish a RFQ notice in at least two national newspapers, company website and preferably in trade magazines also to accord it wide publicity. The bidding shall necessarily be by way of International Competitive Bidding (ICB). For the purpose of issue of RFQ minimum conditions to be met by the bidder shall be specified by the procurer in the RFQ notice.
- 5.3. Procurer shall provide only written interpretation of the tender document to any bidder / participant and the same shall be made available to all other bidders. All parties shall rely solely on the written communication and acceptances from the bidders.
- 5.4. Standard documentation to be provided by the procurer in the RFQ shall include,
- (i) Definition of Procurer's requirements, including:
- Quantum of electricity proposed to be bought in MW. To provide flexibility to the bidders, this may be specified as a range, within which bids would be accepted. Further, the procurer may also provide the bidders the flexibility to bid for a part of the tendered quantity, subject to a given minimum quantity.

- The procurer may separately specify distinct baseload requirements and peakload requirements through the same bid process. Seasonal power requirements, if any, shall also be specified;
 - Term of contract proposed; (as far as possible, it is advisable to go for contract coinciding with life of the project in case of long term procurement). The bidder shall be required to quote tariff structure for expected life of the project depending upon fuel proposed by him. The expected life project is estimated to be 15 years for gas/liquid fuel based projects, 25 years for coal based projects and 35 years for hydro projects.
 - Normative availability requirement to be met by seller (separately for peak and off-peak hours, if necessary);
 - Definition of peak and off-peak hours;
 - Expected date of commencement of supply;
 - Point(s) where electricity is to be delivered;
 - Wherever applicable, the procurer may require construction milestones to be specified by the bidders;
 - Financial requirements to be met by bidders including, minimum net-worth, revenues, etc with necessary proof of the same, as outlined in the bid documents;
- (ii) Model PPA proposed to be entered into with the seller of electricity. The PPA shall include necessary details on:
- Risk allocation between parties;
 - Technical requirements on minimum load conditions;
 - Assured offtake levels;
 - Force majeure clauses as per industry standards;
 - Lead times for scheduling of power;
 - Default conditions and cure thereof, and penalties;
 - Payment security proposed to be offered by the procurer.
- (iii) Period of validity of offer of bidder;
- (iv) Requirement of transfer of assets by the selected bidder (if any) to the procurer at the end of the term of the PPA.
- (v) Other technical, operational and safety criteria to be met by bidder, including the provisions of the IEGC/State Grid Code, relevant orders of the Appropriate Commission (e.g – the ABT Order of the CERC), emission norms, etc., as applicable.

- (vi) The procurer may, at his option, require demonstration of financial commitments from lenders at the time of submission of the bids. This would accelerate the process of financial closure and delivery of electricity;
- (vii) The procurer and the supplier may exercise exit option subject to the condition that the new player satisfies all RFP conditions.

5.5. RFP shall be issued to all bidders who have qualified at the RFQ stage. In case the bidders seek any deviations and procurer finds that deviations are reasonable, the procurer shall obtain approval of the Appropriate Commission before agreeing to deviation. The clarification/revised-bidding document shall be distributed to all who had sought the RFQ document informing about the deviations and clarifications. Wherever revised bidding documents are issued, the procurer shall provide bidders at least two months after issue of such documents for submission of bids.

5.6. Standard documentation to be provided by the procurer in the RFP shall include,

- (i) Structure of tariff to be detailed by bidders;
- (ii) **PPA proposed to be entered with the selected bidder.**

The model PPA proposed in the RFQ stage may be amended based on the inputs received from the interested parties, and shall be provided to all parties responding to the RFP. No further amendments shall be carried out beyond the RFP stage;

- (iii) **Payment security to be made available by the procurer.**

The payment security indicated in the RFQ stage could be modified based on feedback received in the RFQ stage. However no further amendment to payment security would be permissible beyond the RFP stage.

- (iv) **Bid evaluation methodology to be adopted by the procurer including the discount rates for evaluating the bids.**

The bids shall be evaluated for the composite levellised tariffs combining the capacity and energy components of the tariff quoted by the bidder. In case of assorted enquiry for procurement of base load, peak load and seasonal power, the bid evaluation for each type of requirement shall be carried out separately. The capacity component of tariffs may feature separate non-escalable (fixed) and escalable (indexed) components. The index to be adopted for escalation of the escalable component shall be specified in the RFP. For the purpose of bid evaluation, median escalation rate of the relevant fuel index in the international market for the last 30 years for coal and 15 years for gas / LNG (as per CERC's notification in (vi) below) shall be used for escalating the energy charge quoted by the bidder. However this shall not apply for cases where the bidder quotes firm energy charges for each of the years of proposed supply, and in such case the energy charges proposed by the bidder shall be adopted for bid evaluation. The rate for discounting the combination of fixed and variable charges for computing the levellised tariff shall be the prevailing rate for 10 year GoI securities;

- (v) The RFP shall provide the maximum period within which the selected must commence supplies after the PPA is entered into by the procurer with the selected bidder, subject to the obligations of the procurer being met. This shall ordinarily not be less than four years from the date of signing of the PPA with the selected bidder in case supply is called for long term procurement. The RFP shall also specify the liquidated damages that would apply in event of delay in supplies.
- (vi) Following shall be notified and updated by the CERC every six months for the purpose of bid evaluation:
1. Applicable discount rate
 2. Escalation rate for coal
 3. Escalation rate for gas /LNG
 4. Inflation rate to be applied to indexed capacity charge component.

Bid submission and evaluation

- 5.7. To ensure competitiveness, the minimum number of qualified bidders should be at least two other than any affiliate company or companies of the procurer. If the number of qualified bidders responding to the RFQ/RFP is less than two, and procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission.
- 5.8. Formation of consortium by bidders shall be permitted. In such cases the consortium shall identify a lead member and all correspondence for the bid process shall be done through the lead member. The procurer may specify technical and financial criteria, and lock in requirements for the lead member of the consortium, if required.
- 5.9. The procurer shall constitute a committee for evaluation of the bids with at least one member external to the procurer's organisation and affiliates. The external member shall have expertise in financial matters / bid evaluation. The procurer shall reveal past associations with the external member - directly or through its affiliates - that could create potential conflict of interest.
- 5.10. Eligible bidders shall be required to submit separate technical and price bids. Bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee along with the bids. Adequate and reasonable bid-guarantee shall be called for to eliminate non-serious bids. The bids shall be opened in public and representatives of bidders desiring to participate shall be allowed to remain present.
- 5.11. The technical bids shall be scored to ensure that the bids submitted meet minimum eligibility criteria set out in the RFP documents on all technical evaluation parameters. Only the bids that meet all elements of the minimum technical criteria set out in the RFP shall be considered for further evaluation on the price bids.

- 5.12. The price bid shall be rejected if it contains any deviation from the tender conditions for submission of price bids.
- 5.13. Wherever applicable, the price bid shall also specify the terminal value payable by the Procurer for the transfer of assets by the selected bidder in accordance with the terms of the RFP.
- 5.14. The bidder may quote the price of electricity at the generating station bus-bar (net of auxiliaries), or at the interface point with the State transmission network. For purposes of standardization in bid evaluation, the tariffs shall be compared at the interface point of the generator/supplier with the State transmission network. In case the bidder quotes his rate at the generating station bus-bar, normative transmission charges for the regional/inter-regional network, if applicable, based on the prevailing CERC orders shall be added to the price bid submitted. The charges for the State transmission network shall be payable by the procurer, and shall not be a part of the evaluation criteria.
- 5.15. The bidder who has quoted lowest levelled tariff as per evaluation procedure, shall be considered for the award. The evaluation committee shall have the right to reject all price bids if the rates quoted are not aligned to the prevailing market prices.

Deviation from process defined in the guidelines

- 5.16. In case there is any deviation from these guidelines, the same shall be subject to approval by the Appropriate Commission. The Appropriate Commission shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 90 days.

Arbitration

- 5.17. The procurer will establish an Amicable Dispute Resolution (ADR) mechanism in accordance with the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. The ADR shall be mandatory and time-bound to minimize disputes regarding the bid process and the documentation thereof.

If the ADR fails to resolve the dispute, the same will be subject to jurisdiction of the appropriate Regulatory Commission under the provisions of the Electricity Act 2003.

Time Table for Bid Process

- 5.18. A suggested time-table for the bid process is indicated below. The procurer may give extended time-frame indicated herein based on the prevailing circumstances and such alterations shall not be construed to be deviation from these guidelines.

Event	Elapsed Time from Zero date
Publication of RFQ	Zero date
Submission of Responses of RFQ	60 days
Shortlisting based on responses and issuance of RFP	90 days
Bid clarification, conferences etc	150 days
Final clarification and revision of RFP	180 days
Technical and price bid submission	360 days
Shortlisting of bidder and issue of LOI	390 days
Signing of Agreements	425 days

5.19 A suggested time-table for the Single stage bid process is indicated below. The procurer may give extended time-frame indicated herein based on the prevailing circumstances and such alterations shall not be construed to be deviation from these guidelines.

Event	Elapsed Time from Zero date
Publication of RFP	Zero date
Bid clarification, conferences etc. & revision of RFP	90 days
Technical and price bid submission	180 days
Short-listing of bidder and issue of LOI	210 days
Signing of Agreements	240 days

6. Contract award and conclusion

- 6.11. The PPA shall be signed with the selected bidder consequent to the selection process in accordance with the terms and conditions as finalized in the bid document before the RFP stage.
- 6.12. Consequent to the signing of the PPA between the parties, the evaluation committee shall provide appropriate certification on adherence to these guidelines and to the bid process established by the procurer.

- 6.13. The procurer shall make evaluation of bid public by indicating terms of winning bid and anonymous comparison of all other bids. The procurer shall also make public all contracts signed with the successful bidders.
- 6.14. The final PPA along with the certification by the evaluation committee shall be forwarded to the Appropriate Commission for adoption of tariffs in terms of Section 63 of the Act.

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.